रपट

लोकनीति संवाद

अक्तूबर - नवम्बर, 2022

विद्या आश्रम
सारनाथ, वाराणसी

रपट: लोकनीति संवाद

अक्टूबर – नवम्बर 2022

लोकनीति संवाद -1

नगर के अस्सी घाट पर रविवार 11 अक्तूबर 2022 को लोकनीति-संवाद का आयोजन हुआ. **स्वराज अभियान के रामजनम** ने विषय का परिचय कराते हुए लोकनीति-संवाद की ज़रूरत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में ज्ञान की उन धाराओं को, जो लोकहित में हैं, जीवंत हैं, और नैतिक शक्तियों को बल प्रदान करती हैं, उन्हें पहचानना और समाज के बीच लाना आवश्यक है। जल्दी ही वाराणसी नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में हमारे सभासद लोकहित में किस तरह की नीतियां बनायें और अमल करें, इस पर सार्वजनिक संवाद होना चाहिए। **किसान, कारीगर, मज़दूर, पटरी, ठेलेवाले यानि लोकविद्या-समाज के ज्ञानी, पढ़े-लिखों की बराबरी से जब इस संवाद में शामिल होंगे तभी 'कारगर नैतिक लोकनीति' को आकार मिल सकेगा.**

लोकविद्या जन आन्दोलन की संयोजक चित्रा सहस्रबुद्धे ने कहा कि लोकनीति के मायने प्रकृति के साथ तालमेल में जीवन को गढ़ने के प्रकारों में हैं. राजनीति और लोकनीति में विरोध है. लोकनीति में सम्पूर्ण लोक को खुशहाल बनाने की नीतियां हैं और राजनीति मात्र कुछ लोगों के स्वार्थ को पूरा करती रही है. सामान्य लोगों के पास ज्ञान है और इनके ही जीवन में समकालीन नैतिक मूल्य भी पलते हैं. इन्हीं के बल पर लोकनीति को गढ़ा जा सकता है. अगले ही महीने वाराणसी नगर निगम के चुनाव होने हैं. चुनाव लड़ने वालों से यह संवाद किया जाना चाहिए कि वे लोकनीति को मज़बूत करेंगे या राजनीति को ? **तर्क संगत तो यही है कि वाराणसी के स्थानीय निकायों की व्यवस्थाओं में वाराणसी-लोक की खुशहाली को प्रधानता मिलनी चाहिए.** वाराणसी के सभी लोगों और समाजों से हमारी अपील है कि वे इस लोकनीति-संवाद में शामिल होकर लोक की खुशहाली के रास्ते बनाने में योगदान करें.

भारतीय किसान यूनियन के वाराणसी नगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने कहा कि हाल ही में हुए किसान आन्दोलन ने 'न्याय, त्याग और भाईचारा' जैसे नैतिक मूल्यों को स्थापित कर लोकनीति की बुनियाद बना दी है. इन मूल्यों पर आधारित लोकनीति ही राजनीति को मर्यादित कर नैतिक पथ पर ला सकती है.

अध्यक्षता कर रही कारीगर नजरिया की प्रेमलताजी ने कहा कि लोकविद्या ही लोकनीति का निर्माण करती है और लोकनीति पुनः लोकविद्या को नवीन कर मज़बूत बनाती है. इस बात को अगर समझें तो सामान्य किसान-कारीगर समाजों में बसी नैतिक शक्ति का प्रवाह पुनर्जीवित हो उठेगा. उन्होंने कहा कि लोकनीति-संवाद की ये कड़ियाँ आगे जारी रहेंगी और अगला संवाद राजघाट पर गुरुवार को होगा. संवाद में लक्ष्मण प्रसाद, कमलेश, सरविन्द पटेल और सामू भगत ने भी अपनी बात रखी.

पिछले सौ वर्षों में भारत में राज्य की अवधारणा को विभिन्न जन आन्दोलनों से आये मूल्यों ने प्रभावित किया है. इन्हें नीचे दिए बिन्दुओं में लिखा है. लोकनीति पर विचार करते समय शायद इससे मदद मिले.

- **यूरोपीय प्रबोधन से आये — समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व**
- **गांधीजी के नेतृत्व में आज़ादी-आन्दोलन से आये — सत्य, अहिंसा और स्वदेशी**
- **हाल ही के किसान आन्दोलन से आये — न्याय, त्याग और भाईचारा**
- **नफ़रत छोड़ो-भारत जोड़ो अभियान के दौरान — तार्किकता, क्षेत्रीयता, सामाजिक -न्याय**

लोकनीति संवाद-2

वाराणसी नगर निगम के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में वाराणसी ज्ञान पंचायत की ओर से चलाये जा रहे लोकनीति-संवाद की दूसरी कड़ी गुरुवार के दिन शाम 4.00 बजे राजघाट पर सम्पन्न हुई. वक्ताओं में **वार्ड 63 जलालीपुरा** (कज़्जाक पुरा रेल लाइन से वरुणा नदी) **से सभासद उम्मीदवार फज़लुर्रहमान अंसारी, वाराणसी आटोचालक यूनियन के संयोजक ज़ुबेर खां, राजघाट के नाविक दुर्गा प्रसाद साहनी, भाकियू वाराणसी नगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता आमंत्रित थे.** स्वागत और संचालन गोरखनाथ जी ने किया. लोकविद्या सत्संग के साथ संवाद शुरू हुआ.

नगर निगम की जिम्मेदारियों और सभासद के कर्तव्य पर विस्तार से अपनी बात रखते हुये **अंसारी महोदय** ने कहा कि वार्ड के निवासियों के प्रति उस वार्ड के सभासद का नैतिक दायित्व है और नगर निगम द्वारा वार्ड के लिए किये जा रहे काम निवासियों का अहित न करें इसके प्रति उसे सचेत रहना चाहिए. इसके लिए वार्ड के निवासियों के बीच संवाद और सहजीवन के मूल्यों की स्थापना पहला कार्य होना चाहिए, जिसके चलते पैसे के बल पर बढ़ती अनैतिक शक्ति, भ्रष्टाचार, व अव्यवस्था को रोका जा सके. उन्होंने कहा कि इस दिशा में वे अपने कार्य तय करेंगे और इस नगर की विविधता के बीच सहजीवन की परम्परा को मज़बूत करने की ओर कदम बढ़ायेंगे. उनका सुझाव था कि हर वार्ड में एक वार्ड पंचायत होनी चाहिए.

खां साहब का कहना था कि नगर निगम जब आटो स्टैंड का ठेका देता है तब आटो चालकों से संवाद कर उनकी परेशानियों और सुझावों को लेना चाहिए. हर वार्ड में परिवहन की व्यवस्था के लिये वहां के सभासद की ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए. राजघाट के **नाविक श्रीमान दुर्गा प्रसाद** ने नाविकों की समस्याओं को बहुत ही स्पष्टता से सबके सामने रखा. नगर निगम की नीतियां प्रदूषण और सुंदरीकरण के नाम पर लोगों के मुंह का निवाला छीनने और उनके घरों को उजाड़ने की कैसे हो सकती हैं? इस नगर की परम्परा तो सबको अन्न खिलाने और शामिल कर लेने की रही है. हम नाविकों के साथ निगम का यह व्यवहार इस नगर की परम्परा का निर्वाह करने में सर्वथा असफल है.

कृष्ण कुमार जी ने कहा कि गंगा जी और गंगा जी के घाट कैसे स्वच्छ और निर्मल रहें इसके लिये यहां के किसान, कारीगर और नाविकों से ही सही राय मिलेगी जिन्होंने सदियों से ऐसा कर दिखाया है, ना कि कारपोरेट कम्पनियों से.

चित्रा जी ने कहा कि नगर निगम और सभासद नागरिकों की सेवा के लिये हैं. नगर के राजा तो यहां के नागरिक ही हैं. इस रिश्ते को वास्तविक बनाने की दिशा खोजना ही लोकनीति-संवाद का लक्ष्य है.

संवाद के दौरान सभी वक्ताओं ने कहा कि चुनाव के बाद सभी प्रतिनिधि नागरिकों से मुंह फेर लेते हैं. ऐसी नशे में चूर राजनीति का इलाज भी क्या है? लोकनीति की भूमिका उस महावत की है जो पगलाये हाथी को काबू करता है.

लोकनीति संवाद-3

अस्सी घाट पर रविवार की सुबह 8 .00 बजे से लोकनीति संवाद शुरू हुआ. संवाद की शुरुआत छात्र प्रत्युष के बांसुरी वादन से हुई. बांसुरी से निकलती 'वैश्नव जन तो तेने कहिये...' की मधुर, शांत और गंभीर धुन सुबह के वातावरण में धीरे-धीरे घुलने लगी. सुरों के सात्विक जादू में बंध कर अगल-बगल के लोग लोकनीति-संवाद के पास खिंचे चले आये.

संवाद में मुख्य वक्ता के रूप में 'गाँव के लोग' वेब पत्रिका के संपादक रामजी यादव थे और **विषय था---वाराणसी नगर निगम की ज़िम्मेदारी के सन्दर्भ में गाँव और शहर के बीच सम्बन्ध कैसा होना चाहिए.**

सामू भगत और सरविन्द पटेल की सदारत में लोकविद्या के बोल गाने के बाद अपने अन्दर, समाज के अन्दर और वाराणसी नगर की परंपरा में निहित शक्तियों को जानने का आवाहन करते हुए 'जान ले रे दीवाना, अब जान ले...' पद गाया गया.

स्वराज अभियान के रामजनम ने सञ्चालन का ज़िम्मा लेकर संवाद की शुरुआत की. विषय प्रवेश में कहा गया कि लगभग हर जिले में गाँव और शहर के बीच का सबंध एकतरफा है. शहर गाँवों से सारे संसाधन तो उठाता है और बदले में क्या देता है तो शहरभर का कूड़ा, बदहाली और ज़लालत. ऐसे में नगर निगम की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? गाँव से शुद्ध अन्न, फल और सब्जियां, तथा अनेक वस्तुयें और उनके कच्चे माल शहर में आते हैं पर शहर उन्हें प्रदूषित हवा, जल और मिलावटी सामान देता है, कृषि भूमि के अधिग्रहण का दर्द तो अलग है ही.

रामजी यादव ने कहा कि यह बात बिलकुल सही है कि यह रिश्ता जब तक बराबरी का नहीं होगा तब तक न शहरों की समस्या सुलझेगी और न गाँवों की. इस रिश्ते को न्यायपूर्ण बनाने में नगर निगम की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए. उन्होंने गाँव के लोगों के जीवन की, उनके ज्ञान और जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता को विस्तार से रखते हुए कहा की यह धरती तो गाँवों की सभ्यता का आधार लेकर ही हरी-भरी रह सकती है न कि कारपोरेट आधारित तकनीकी और विकास के बल पर.

'लोक' की खुशहाली के लिए कार्पोरेट आधारित तकनीकी और प्रबंधन की भूमिका का पैमाना तय होना ज़रूरी है. वे कुछ ही लोगों के विलास के लिए वस्तुओं के उत्पादन के हिमायती हैं और इसके लिए हर तरह का असंतुलन (समाज में और प्रकृति में) पैदा करने में नहीं हिचकते. आज गाँव और शहर के बीच एकतरफा रिश्ते का आधार भी इसमें ही है. हर छोटे बड़े निर्माण अथवा कार्य और क्रियाओं के लिए अगर कार्पोरेट आधारित तकनीकी और प्रबंधन का इस्तेमाल होने लगेगा तो निश्चित ही शहर और गाँव दोनों कंगाल ही होंगे. **ऐसे में किसी भी कार्य के लिए तकनीकी कौनसी हो (लोकविद्या आधारित या कार्पोरेट आधारित) इसके बारे में हर स्तर पर सघन संवाद और विमर्श की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि लोकनीति-संवाद शहर और गाँव दोनों में हों और इसमें वे भी शामिल होंगे.**

भाकियू के कृष्णकुमार ने कहा कि प्रशासन और 'लोक' के बीच सम्मान पूर्ण संवाद होना ज़रूरी है, नगर निगम में तो जन प्रतिनिधि हमीं चुनकर भेजते हैं. हमारे सामने जीवंत उदहारण है किसान आन्दोलन का, जिसने किसानों के खिलाफ लाये तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए केन्द्रीय सरकार को बाध्य किया है. लोक और समाज में ये संवाद कैसे हो इस बारे में इस नगर के सभी ज्ञानी लोगों की अपनी-अपनी राय होगी लेकिन इन सभी राय को विमर्श में ले आने का माहौल बनाना चाहिए. सभी तबके जब गाँव-शहर के बीच रिश्तों के संतुलन को हासिल करने के विमर्श में शामिल होंगे तभी खुशहाल, स्वच्छ और सभ्य नगर बनाने के रास्ते खुलेंगे.

यह भी बात हुई की नगर निगम को सेल्फ गवर्नंस (स्वशासन) की स्थानीय इकाई के रूप में मान्यता है लेकिन नगर निगम के चुनावों को राजनीति का अखाड़ा बना देने से यह हो नहीं पाता है. निगम के विचार और कार्यों में स्थानीय लोगों की भूमिका का महत्त्व तेज़ी से घटता ही जाता है. नगर की अवधारणा, उसके प्रशासन का प्रकार, विकास के बारे में

दृष्टिकोण, बाज़ार की चमक से प्रभावित होने की प्रवृत्ति आदि का आधार जिस ज्ञान के दबदबे में आकार ले रहा है, उसमें लोक, लोकसमाज और उनके जीवन को कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है. इसे ही बदलना ज़रूरी है.

प्रेमलताजी ने कहा कि विकास के सारे कार्य सामान्य लोगों की सुविधा के लिए नहीं होते है और ये अभी ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के ज़माने से ऐसा ही हुआ है. रेल जनता के लिए नहीं बल्कि अँगरेज़ सेना, बड़े उद्योगों के लिए कच्चे माल और उत्पादन के द्रुत स्थानांतरण के लिए बनी. आज के फ्लाई ओवर भी सामान्य जनता के लिए नहीं बल्कि मोटर वालों के लिए और मोटरों की खपत बढ़ाने के लिए बनाये गये हैं.

अस्सी के निवासी निषाद देशराज ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि यह बात सही है कि पक्के घाटों की संख्या बढ़ गई लेकिन हमारी आमदनी घट गई, यह कैसा विकास है? प्रत्युष ने कहा कि जिस तरह विद्यालयों में सभी को साइंस पढाया जाता है उस तरह संगीत भी पढ़ाया जाए तो मनुष्य के अन्दर की संवेदनाओं को जगाया और विकसित किया जा सकता है. तब शायद समाज में विकास के नए और अधिक मानवीय मूल्य स्थापित होने के रास्ते भी बन सकेंगे.

इसके बाद विद्या आश्रम द्वरा प्रकाशित पुस्तक 'न्याय, त्याग और भाईचारा : किसान आन्दोलन और भावी समाज दृष्टि' पुस्तक गोंव के लोग' पत्रिका के संपादक श्री रामजी यादव को भेट की गई.

इस संवाद में अभिषेक, छोटेलाल, मु. अलीम, छित्तुपुर निवासी लक्ष्मण, अपर्णा, सामू भगत, सरविन्द पटेल, देशराज निषाद, प्रत्युष, और चित्रा सहस्रबुद्धे ने अपने विचार रखे. संवाद के अंत में प्रत्युष ने बांसुरी पर राग अहीर भैरव की तान सुनाई और संवाद को संकल्प का रूप देने का संकेत दिया.

लोकनीति संवाद - 4

गुरूवार राजघाट

लोकनीति संवाद की चौथी कड़ी, गुरुवार शाम 4.00 बजे राजघाट पर आयोजित हुई. वाराणसी नगर निगम के अगले महीने नवम्बर में होने जा रहे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में संवाद आगे बढ़ा. स सामू भगत, छोटेलाल राजभर और सरविन्द पटेल की सदारत में लोकविद्या सत्संग शुरु हुआ.

आज के संवाद में सलारपुर के श्री महेन्द्र प्रताप मौर्य और आलमपुरा के जनाब एहसान अली मुख्य थे. सलारपुर गाँव शहर के उत्तर में दीनापुर गंगा प्रदूषण प्लांट से सटा गाँव है और नगर निगम क्षेत्र में आये इस गाँव को लगभग 8-10 वर्ष हो चुके हैं. आलमपुरा शहर के मध्य में है और कारीगरों का सघन निवास स्थान है.

दोनों ही वक्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्र में नगर निगम की भूमिका पर बात रखी. महेन्द्र प्रताप मौर्य ने कहा कि निगम नये शामिल किये गाँवों से कर तो वसूलता हैं पर सुविधायें उपलब्ध नही कराता. गृह कर ऐसे लोगों पर लगा दिया जो जिन्दगी भर बस एक कमरा ही बना पाये हैं. इसका भी ज़िक्र आया कि पेयजल, सीवर, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य किसी भी क्षेत्र में हमारे सभासद और निगम ज़िम्मेदारी निभाने में सक्षम नज़र नही दिखते. कम से कम निगम तब तक कोई कर न ले जब तक बस्तियों में ये सुविधाएं न हो जाये.

चर्चा से यह बात भी उठी कि इस अक्षमता के अनेक कारण हो सकते हैं लेकिन उनमें से एक कारण यह भी है कि निगम स्थानीय निवासियों के ज्ञान, हुनर और क्षमताओं को नज़रअंदाज़ करता है और बड़ी कम्पनियों की महंगी तकनीकी और प्रबंधन के सहारे परियोजनाओं को चलाने को वरीयता देता है. इसकारण स्थानीय लोगों के रोज़गार खतरे में पड़ जाते हैं. यह बात भी हुई कि शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म जैसे क्षेत्रों को बाजार बना देना 'विकास' कैसे कहा जा सकता है?

सरविन्द ने 'जागु जागु जंजाली मनवा, यह तो मेला हाट का... ' पद गाकर आज के बाजार के अमानवीय रूप को उजागर कर इसके बंधन से निकलने का आवाहन किया.

एहसान अली ने कहा कि आलमपुरा जैसे सघन इलाकों में पेयजल और सीवर की लचर व्यवस्थायें नागरिकों के स्वास्थ्य और रोजगार को सीधे प्रभावित करती हैं. बुनकरों की इस सघन बस्ती में बारिश के चलते करघे सीवर के पानी में डूब जाते हैं. नालियों की बदहाली और सफाई की क्या बात करें?

संवाद के दौरान वाराणसी ज्ञान पंचायत की ओर से प्रकाशित पत्रक 'सुर साधना' का दूसरा अंक रखा गया और वाराणसी की परम्पराओं की बात में वाराणसी के नगर निवासियों द्वारा अंग्रेजों ने लगाये गृहकर के खिलाफ 1810 में किये असहयोग आन्दोलन पर चर्चा हुई.

फज़लुर्रहमान अंसारी ने कहा कि निगम को स्थानीय संसाधनों को वरीयता देना चाहिए. कच्चा माल, श्रम, ज्ञान, तकनीकी, सभी में स्थानीय लोगों की शिरकत बढ़ाने की नीति होनी चाहिए. केवल वही बाहर से हो जो यहां नही होता तभी यह नगर सुंदर और खुशहाल होगा.

संवाद का संचालन कृष्णकुमार ने किया.

लोकनीति संवाद - 5, 6, 7

वाराणसी ज्ञान की नगरी मानी जाती है. हर युग में विविध दर्शन, धर्म और विचार के ज्ञानी यहाँ आते रहे हैं. वाराणसी में गंगाजी के घाट मात्र मनोहारी दृश्य का सुख लुटाने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान चर्चा के ठीये माने जाते रहे हैं. इसी परम्परा में इन घाटों पर लोकविद्या सत्संग होता है.

नवम्बर 2022 में वाराणसी नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं. इन चुनावों के सन्दर्भ में वाराणसी ज्ञान पंचायत की पहल पर लोकविद्या सत्संग के साथ 'लोकनीति-संवाद' के नाम से नगरवासियों के बीच एक संवाद श्रंखला चलाई जा रही है. अब तक इस संवाद की पांच कड़ियाँ हो चुकी है और गत रविवार 6 नवम्बर 2022 को छठी कड़ी का आयोजन हुआ.

लोकनीति संवाद की इस कड़ी का विषय था 'पर्यावरण प्रदूषण और नगर निगम की ज़िम्मेदारी'

लोकनीति-संवाद 6 में पर्यावरण प्रदूषण पर कार्य करने वाले एकता शेखर और रवि शेखर, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध छात्र पुनीत शामिल हुए.

लोकविद्या के बोल गाकर सामू भगत ने लोकविद्या के दावे ठोकने का आवाहन किया और इसके बाद संवाद को खोलते हुए **भारतीय किसान यूनियन के वाराणसी नगर अध्यक्ष कृष्णकुमार** ने कहा कि शुद्ध-जल के नाम पर जल का बाजारीकरण कर दिया गया है. नगर निगम नदियों और टंकियों को स्वच्छ नहीं रख पातीं और जल के इस बाजारीकरण को प्रोत्साहित करती हैं. स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी अनेक कार्यों को करना नहीं जानते और ऐसे में वे स्थानीय ज्ञानी-कारीगरों को दिहाड़ी पर लेकर काम करवाते हैं; गाँव में नहर की देखरेख का काम हो या गंगाजी में डूबे लोगों को बचाने की बात हो या बिजली के खम्भों पर तारों की मरम्मत के काम हों, सभी जोखिम भरे काम दिहाड़ी पर यानि बेगारी (सस्ते) में कर लिए जाते हैं. यह लोकविद्या और लोकविद्याधर समाजों को अपमानित करना ही तो है. गंदे पेयजल की आपूर्ति, नालियों के जाम होने और सड़क पर गन्दा पानी फ़ैलने, कूड़ा निस्तारण आदि में कहीं भी सभासद अथवा प्रशासक कभी कटघरे में नहीं आते. ऐसे में समाज को लोकनीति के विचार को पुष्ट करने के रास्ते बनाने होंगे.

चित्राजी ने कहा कि यह सवाल महत्वपूर्ण है कि नगर में अनेक विभागों से सजे ज्ञान के गढ़ के रूप में पांच विश्वविद्यालय हैं और अनेक कालेज भी हैं, उनका नगर निगम की भूमिका को सरल बनाने में कितना सहयोग हो पाता है? नगर के पर्यावरण प्रदूषण का हल खोजने में नगर के शिक्षा संस्थान, प्रशासन और जन प्रतिनिधियों से नगर निवासी क्या उम्मीद रखते हैं? क्या शहर का आधुनिक प्रोफेशनल समाज (छात्र, अध्यापक, सरकारी कर्मचारी आदि) सभासदों से वार्ता कर सस्ती, कारगर और लोकपरक तकनीकियाँ इजाद नहीं कर सकता? क्या वर्षों तक इस नगर में निवास करने के बावजूद इन प्रोफेशनल समाजों का ज्ञान क्या केवल वैश्विक सेवाओं के लिए ही होता है?

वाराणसी के रवि शेखर खुद एक स्वयंसेवी पर्यावरण देखभाल संगठन के संयोजक हैं. नगर के वायु प्रदूषण के क्षेत्र में नगर निगम की जिम्मेदारियों

के सन्दर्भ में **रवि शेखर** ने सरकारी नीतियों को सामने लाया और कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 17 शहरों के वायु प्रदूषण की जांच व नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सरकार ने नगर निगमों को अतिरिक्त धनराशि, प्रत्येक को लगभग 81 करोड़ रुपये, उपलब्ध कराई है. इसके तहत प्रदूषण सेंसर लगाये गए हैं. लेकिन प्रशासक और सरकारी विभाग इसके आंकड़ों को सही नहीं मानते, क्या किया जाए? पर्यावरण के लिए नगर निगम के साथ लगभग 16-17 स्थानीय निकायों/विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने की बात भी है लेकिन यह होता देखा नहीं गया. यह बात भी है कि केन्द्रीय सरकारें जितनी धनराशी योजनाओं के तहत देती हैं उसके खर्च करने में प्राथमिकता नगर निवासियों का हित न होकर राजनीति ही अधिक हावी रहती है.

एकता शेखर ने कहा कि गाँवों में घरों से निकले कूड़े का प्रबंधन कुछ इस तरह होता है कि बड़े पैमाने पर कही एकत्र होने ही नहीं दिया जाता और अलग-अलग ढंग से इस्तेमाल में आ जाता है. शहर के लोग गाँवों के इस ज्ञान से सीख लेना क्यों नहीं चाहते? सभासदों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापूर भेजा जाता है लेकिन उन्हें गाँवों में क्यों नहीं भेजा जाता? क्यों नहीं वे आदिवासियों से नदी को स्वच्छ रखना सीखते हैं ? उन्होंने उदहारण देकर इस बात को लाया किज्ञान कही से भी आया हो अगर पर्यावरण को स्वस्थ और स्वच्छ बनाये रखने में वो कारगर हैं तो उसे अपनाने में क्या हर्ज़ है? और फिर ये तकनीकियां सस्ती और हमारी संस्कृति के अनुकूल भी हैं.

संवाद में यह उभर कर आया कि पर्यावरण और समाज के बीच के रिश्तों का ज्ञान और समझ सामान्य नागरिकों के पास भी होती है, लेकिन उसकी स्थानीय निकाय, प्रशासक आदि उनके ज्ञान और समझ को अवैज्ञानिक कहकर ख़ारिज कर देते हैं. सामान्य नागरिकों के ज्ञान की भूमिका शामिल करने की नीतियाँ बनानी होंगी, अनेक टिकाऊ और कारगर विकल्प उभर कर आयेंगे.

दिल्ली से आये शोध छात्र पुनीत ने जल प्रबंधन को संवाद में लाया. उन्होंने राजस्थान में 'जोहड़' बना कर वर्षा के जल के संग्रह की पारंपरिक तकनीकी के बारे में जानकारी को रखा और कहा कि नगर निगम की भूमिका को तय करने में ऐसे प्रयास मददगार होंगे जिनका निर्माण समाजों की पहल पर होता हैं और उनका रखरखाव भी समाज द्वारा ही संयोजित होता है. नगर की जल भराव की समस्या का हल अकेले जल-इंजिनीयर के पास ही नहीं होता, नगर के मल्लाहों के पास भी हल हो सकता है, जो भूमिगत जल धाराओं के साथ बहाव के उपयुक्त ढलानों का जानकार होता है. नगर की कालोनियों और बस्तियों में भवनों के नक़्शे पास करने से पहले इनकी भी राय क्यों शामिल नहीं होती ?

वार्ड 63 के उम्मीदवार **फ़ज़लुर्रहमान अंसारी**, जो स्वयं बुनकर हैं, ने वार्ड के नागरिकों के प्रति सभासद की नैतिक ज़िम्मेदारियों को महसूस करने पर जोर दिया. इस शहर का 'स्वभाव' इस शहर के नागरिक ही गढ़ते हैं, यहाँ के कारीगर, व्यवसाई, छोटे दुकानदार, ठेले-पटरी वाले और इनके बनाये उत्पाद और सेवाएं, इनकी भाषा, व्यवहार और जीवनमूल्यों का शहर के स्वभाव को गढ़ने में गहरा और व्यापक आधार है. इसे महसूस किया जाना चाहिए. अपने क्षेत्र के सामान्य नागरिक से सभासद इन मुद्दों से जुड़ी समस्याएं, सहमति और असहमति को एकत्र करने के लिए बाध्य होना चाहिए.

सभी वक्ताओं ने संवाद को मुखर बनाया और अगल-बगल से आते-जाते लोग कुछ देर ठहर कर इसमें शामिल हुए, कुछ लोगों ने ठहर कर वीडियो लिए और कुछ ने पर्चे और पुस्तिकायें पढ़ने के लिए खरीदी. नगर के बसंत कन्या महा विद्यालय, कमच्छा की छात्रा प्रतिमा ने पूरा संवाद को ध्यान से सुना और फिर अनेक पक्षों पर अपने विचार भी व्यक्त किये. गाँव और शहर के जीवन की तुलना करते हुए कहा कि किताबों के ज्ञान की तुलना में बुजुर्गों से अधिक कारगर और उपयोगी ज्ञान मिलता रहा है. पढ़ाई के दौरान किताब में जो पढ़ते हैं और वास्तविक जीवन में जो देखते हैं उसके अंतर को बहुत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया. रामनगर के कालेज में अध्यापन करने वाली डॉ. चटर्जी ने लोकनीति-संवाद के प्रयास की सराहना की और संवाद के अंत में एक भजन 'माटी कहे कुम्हार से...' भी प्रस्तुत किया. एक अन्य महिला जो कानपूर से सिविल इंजीनयरिंग की शिक्षा लेकर बेतिया (बिहार) के लोकनिर्माण विभाग में कार्यरत हैं, भी पूरे संवाद में शामिल रहीं. उन्होंने कहा कि यहाँ, इस तरह गंभीर विषयों पर खुला संवाद आयोजित करना एक सकारात्मक उम्मीद जगा रहा है.

वास्तविकता यह है कि वाराणसी एक सघन बस्ती वाला नगर है, यहाँ संकरी गलियों का जाल है, जिसके दोनों ओर बड़ी-बड़ी पक्की इमारतें हैं और जिनकी नीचली मंजिलें छोटी-छोटी दुकानों से सजी हुई है. यह केवल पुराने वाराणसी में नहीं बल्कि वरुणा नदी के पार जो नई कालोनियां बनी हैं उनका भी यही चित्र है. वाराणसी के उत्तर, पूरब और दक्षिण में दूर तक कोई बड़ा शहर नहीं है, ऐसे में यह शहर एक बहुत बड़े क्षेत्र के लिए गल्ला मंडी, शिक्षा और चिकित्सा का केंद्र है. केवल चिकित्सा के लिए ही प्रतिदिन हजारों लोग शहर में आते हैं. यहाँ साल भर में करोड़ों तीर्थ यात्री आते हैं, अनेक देवी-देवताओं के मंदिर और दरगाहों के श्रृंगार और मेले लगते रहते हैं. इन सबके साथ अब देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या भी जुड़ गई हैं. ऐसे में वाराणसी नगर निगम की भूमिका बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती है. सफाई, कूड़ा निस्तारण, सीवर, पेयजल, परिवहन, सड़क निर्माण, बाज़ारों की व्यवस्था, भवन और बस्तियों के नक़्शे, जल और खाद्य पदार्थों की शुद्धता, शिक्षा और चिकित्सा की प्राथमिक सुविधाएँ आदि हर मोर्चे पर नगर निगम असहाय-सा जान पड़ता है.

संवाद को सरविंद पटेल और सामु भगत ने 'हम पाई रे अजब जड़ी, लोकविद्या की अजब जड़ी ...' और 'जागु जागु जंजाली मनवा...' पद गाकर जीवंत बनाया. प्रेमलताजी ने एक कविता प्रस्तुत की जिसमें पर्यावरण के विषय को बिरवा और धुआं के बीच संवेदनात्मक संवाद के मार्फ़त व्यक्त किया. संवाद में छोटेलाल राजभर, मु. अलीम, शीला देवी, पार्थ चटर्जी, हरिश्चंद्र बिन्द और रामजनम की भागीदारी रही.

अंत में संवाद का समापन करते हुए चित्रा सहस्रबुद्धे ने कहा कि गाँव और शहर की व्यवस्थाओं को स्वायत्त और भाईचारा आधारित होना चाहिए. फिलहाल तो यह सम्बन्ध नौकर-मालिक का बना रखा है. नगर निकायों के सञ्चालन में सामान्य नागरिकों के ज्ञान की भागीदारी को बढाकर इस सम्बन्ध को भाईचारे का किया जा सकता है.

लोकनीति-संवाद का यह क्रम नगर निगम चुनावों के बाद भी जारी रखा जायेगा और समाज के नैतिक पक्षों को मुखर बनाने के प्रयास होंगे, जिससे लोकनीति पुष्ट हो.

वाराणसी ज्ञान पंचायत की ओर से चित्रा सहस्रबुद्धे.

लोकनीति संवाद-8

गुरुवार, 17 नवम्बर 2022, शाम 4 बजे से

विषय: वाराणसी नगर निगम की ज़िम्मेदारी-विविध समाजों के बीच भाईचारा

वक्ता: डॉ. मुनीज़ा खान, संकाय सदस्य और रजिस्ट्रार, गाँधी विद्या संस्थान

लोकनीति-संवाद की आठवीं कड़ी की शुरुआत लोकविद्या सत्संग के साथ शुरू हुई. नगर निगम की जिम्मेदारियों में एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी समाज के ताने-बाने को बनाये रखने की है. वाराणसी नगरी सदियों से अनेक समाजों, धर्मों, पंथों, सम्प्रदायों, भाषाओं, आस्थाओं और विद्याओं का स्थान रही है तथा इन विविध ज्ञान धाराओं के बीच सहजीवन का जीवंत उदहारण बनी रही. यहाँ तंत्र, वैदिक, बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, इस्लाम, सिख, नाथ, सिद्ध, अघोर, नाथ, कला, यूरोपीय ज्ञान आदि अनेक परम्पराओं के विद्वान आते रहे हैं और इनके विभिन्न काल में बने संस्थान आज भी अस्तित्व रखते हैं. यह नगर इस भूमि की सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान को समग्रता में संजोये हुए है. ऐसे में यहाँ के स्थानीय निकायों विशेषकर नगर निगम की भूमिका बहुत महत्त्व की बनती है. इसी विषय को लेकर डॉ. मुनीज़ा ने अपनी बात शुरू की.

उन्होंने कहा कि किसी नगर का विकास केवल भौतिक विकास नहीं होता. नगर के विकास के मायने तो यहाँ रहने वाले निवासियों की खुशहाली से आँका जाना चाहिए. विकास तो अलग-अलग समाजों के बीच भाईचारा और प्रेम के साथ मिलजुलकर रहने की क्षमता में आँका जाना चाहिए. उन्होंने सामान्य जीवन के अनेक उदहारण देते हुए कहा कि यहाँ किसतरह समाज के सामान्य लोग एकदूसरे के साथ सहयोग से रहते आये हैं. किसान, कारीगर और महिलाओं में जो ज्ञान (लोकविद्या) है, उसका सम्मान बहुधा स्थानीय निकाय नहीं करते. लोकविद्या का विचार एक न्यायपूर्ण और तर्कसंगत विचार है. जब भी नगर में

प्राकृतिक संकट आते हैं तब कई बार इन समाजों के अनुभव कारगर साबित होते हैं. कुछ लोगों की सुविधा और विलास के लिए नगर के ज्ञानी निवासियों का विस्थापन किया जाना बेहद अन्यायपूर्ण और पीड़ादायी है. अपने अनुभव सुनाते हुए कहा कि एक विद्यालय में बच्चों के साथ हुए एक कार्यक्रम के तहत बच्चों को चित्र बनाने के लिए दिया तो एक मुसलमान बच्चे ने शिवलिंग का चित्र बनाया और बोला कि यही तो इस नगर के देव हैं. निगम की यह ज़िम्मेदारी है कि वह इस नगर की परम्परा और संस्कृति को बनाये रखने और निखारने में कदम आगे बढ़ाये. राजनीति अथवा बाज़ार और व्यापार के दबाव में अपने ही लोगों को उत्पीड़ित करने में भागीदार न बने. उन्होंने आग्रह किया कि अपने सभासद और नगर निगम से वार्ता करने में स्त्रियों को आगे आना होगा. हर वार्ड में एक 5-7 स्त्रियों की टीम बनाने की दिशा में सोचा जाना चाहिए, जो ज़मीनी समस्याओं से अवगत होती हैं और अपने परिवार के साथ उसके विकल्प को भी सामने ला सकती हैं.

चित्राजी ने जोड़ा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह भी जानना ज़रूरी है कि धर्म, अर्थ और राजनीति ये जब-जब जैसे-जैसे अधिक संगठित होंगे तो संकुचित भी होते जायेंगे. वे सामाजिक न होकर मात्र संगठन-हित की सेवा में बने रहेंगे.

रामजनम, फ़ज़लुर्रहमान अंसारी और हरिश्चंद्र बिन्द ने अपने-अपने अनुभव रखे.

लोकनीति संवाद – 9

शनिवार, 19 नवम्बर 2022 शाम 4.00 बजे
विद्या आश्रम, सारनाथ

वक्ता: वरिष्ठ पत्रकार एवं 'उड़ता बनारस' के लेखक श्री सुरेश प्रताप सिंह

विद्या आश्रम परिसर पर आयोजित लोकनीति-संवाद की नौवी कड़ी में नगर के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश प्रताप सिंह को आमंत्रित किया गया. 'उड़ता बनारस' नाम से लिखी उनकी पुस्तक वर्ष 2020 में प्रकाशित हुई है. पर्यटन केंद्र बनाने की योजना के तहत वर्ष 2018 से वाराणसी के अलग-अलग स्थानों पर जो तोड़-फोड़ और नवनिर्माण हुआ है उसे इस पुस्तक का विषय बनाया गया है. हर स्थल पर सुरेश जी खुद गए और उस स्थान के इतिहास को और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में फेसबुक पर लिखते रहे हैं. इसी के आधार पर यह पुस्तक बनी है. पुस्तक में कल्पकता है और इसे किसी भी पृष्ठ से पढ़ा जा सकता है. बनारस की इस कहानी को 'गंगा घाटी की पक्काप्पा संस्कृति व सभ्यता' नाम दिया है और इसे हड़प्पा संस्कृति का भाई बनाया है. काव्य और गद्य में लिखे गए छोटे-छोटे प्रसंग वाराणसी के अतीत और वर्तमान को सामने लाते हैं.

लोकविद्या सत्संग के साथ शुरू हुई वार्ता में सुरेश जी ने वाराणसी में भ्रमण के अनुभवों को सामने रखा. विस्थापित परिवारों की व्यथा और स्थानीय निकायों की असंवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए उन्होंने लोकनीति को आकार देने के प्रयासों को आगे ले जाने की आवश्यकता को उजागर किया. उनके वक्तव्य के बाद संवाद में शामिल सभी लोगों ने अपनी जिज्ञासा के प्रश्न पूछे जिससे वाराणसी का अतीत और वर्तमान खुलकर सामने उपस्थित हुआ.

लोकनीति संवाद - 10

रविवार, 20 नवम्बर, 2022, सुबह 8 बजे
अस्सीघाट, वाराणसी

वक्ता: डॉ. पारमिता

लोकनीति संवाद की दसवीं कड़ी में नगर निगम के चुनावों में लोकमत का महत्व चर्चा का विषय बना. डॉ. पारमिता ने वार्ता को नगर निगम के कार्यों, तरीकों और नियमों की व्याख्या करते हुए कहा कि लोकतंत्र के तहत बनी नगर निगम में 'लोक' कहाँ

है? जब यह वार्ता हो रही थी तब कई लोग इसे सुन रहे थे. ऐसे में बारी बारी से एक बुज़ुर्ग और शिवपुर से आई सोनी वर्मा नाम की महिला ने आपत्ति दर्ज की और कहा कि कबीर की आड़ में आप लोग राजनीति कर रहे हैं?

राजा और प्रजा के बीच सम्बन्ध पर वार्ता करना क्या राजनीति हो जाती है? संवाद में कुछ तेज़ी आ गई. अपने मत और आपत्तियां सुनाने के लिए लोग एकत्र होने लगे. एक युवा पुलिस वाले को लेकर आ गया. पुलिस ने कहा कि धारा 144 लगी है और आप लोग बिना अनुमति के यह कैसे कर रहे हैं, इतना कहकर वो चला गया और थोड़ी देर बाद सत्संग फिर शुरू हो गया. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से वेद शिक्षा ले रहे दो छात्र बैठकर पूरी चर्चा सुनते रहे. उन्हीं से पूछा गया कि क्या वेद लिखने-पढ़ने वालों के ज़माने में ज्ञान-चर्चा करने वालों पर राजनीति करने का आरोप लगता रहा है? असमंजस में वे बोले "नहीं ". श्रीमती सोनी वर्मा भी वापस आ गई और उन्होंने भी दो भजन सुनाये. इस पूरे घटनाचक्र को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग से आई छात्रा अन्जु देख-सुन रही थी. अंत में बोली आप लोग सही बात तो कर ही रहे हैं, मुझे तो सुनना बहुत अच्छा लगा.

लोकनीति संवाद-10 की शुरुआत सामू भगत और सरविंद पटेल ने लोकविद्या सत्संग के साथ की और लोकविद्या की महत्ता को सामने लाया. इसे सुनकर कानपुर से अपने बेटे के साथ आई एक महिला ने भजन सुनाया और लोकनीति संवाद में भाग लिया.

हरिश्चंद्र ने संवाद का सञ्चालन करते हुए लोकनीति-संवाद के सन्दर्भ और सार को रखा.

डॉ. पारमिता ने कहा कि नगर के निर्माण में विशेषकर पिछले कुछ वर्षों से लोकमत और लोकविद्या को पूरी तरह नकारा जा रहा है. सभासदों के चुनाव, उनके कार्य और कार्य पद्धति में स्थानीय लोगों की राय का समावेश नहीं होता. पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से पिछले वर्ष गंगाजी के रेतीले तट के हिस्से पर एक रेत की नहर का निर्माण हुआ कि उसमें जहाज चलेंगे. इस वर्ष की बाढ़ में वह नहर पूरी बह गई. घाटों पर बाढ़ से आई मिट्टी को हटाने के लिए बिजली के कई पम्प लगाकार पानी खींचा जाता है और इसकी सहायता से जमा मिट्टी को वापस गंगाजी में बहाया जाता है. स्थानीय मल्लाहों के अनुसार यह तरीका गलत है लेकिन निगम सुनता ही नहीं. मोहल्लों की सफाई के लिए और कूड़ा निस्तारण की तकनीकी सीखने के लिए सभासदों को जापान भेजा जाता है लेकिन स्थानीय नागरिकों से सलाह करने का समय नहीं है. क्या यह लोकतंत्र कहा जायेगा?

लोकनीति संवाद – 11

शनिवार, 26 नवम्बर 2022
विद्या आश्रम, सारनाथ

वक्ता: अनूप श्रमिक, मनीष शर्मा और जाग्रति राही

विषय: नगर निगम और प्रशासन के बीच रिश्ता और कारीगर बस्तियों में नगर निगम की भूमिका.

विद्या आश्रम में हुए इस संवाद की शुरुआत श्याम नारायण और सरविंद पटेल के लोकविद्या संवाद की गायकी से हुई. इसके बाद चित्राजी ने संवाद के विषय को खोला और कहा कि नगर निगम पर नगर की व्यवस्था के निर्माण और देखभाल की ज़िम्मेदारी की है. अपेक्षा यह है कि नगर निगम और सभासद नगर निवासियों के साथ सीधे संवाद में शामिल हों और निगम के सदन में उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं और सुविधाओं पर अधिक बात हो. लेकिन नगर के प्रशासनिक विभाग नगर निगम, उसके सहयोगी विभाग और सभासदों (जन प्रतिनिधियों) को कोई तवज्जो नहीं देते. ऐसे में नगर निवासी लाचार हो जाते हैं. निगम की निवासियों के साथ सहयोग की धारा कैसे बने इस पर हर ढंग से सोचने की ज़रूरत है.

अनूप श्रमिक ने कहा कि नगर पालिका और नगर निगमों की व्यवस्था को देश के लगभग सभी राज्यों की विधान सभाओं ने 1959 के बाद हुए संशोधन पारित कर लागू किया है. उत्तर प्रदेश और बिहार में

ऐसा नहीं हुआ और इसकी वजह से यहाँ के नगर निकायों की स्थिति बहुत ख़राब है. कई वर्षों तक तो चुनाव ही नहीं हुए और अब होने लगे हैं तो बजट की कमी और पार्षदों की गैर-ज़िम्मेदारी के चलते सब कुछ लचर अवस्था में पहुँच गया है. अन्य राज्यों में इतनी बुरी हालत नहीं है. वाराणसी में पिछले 20-25 वर्षों से भाजपा का ही मेयर रहा है. विकास के कार्य कैसे हो, उनकी गुणवत्ता कैसी है आदि जैसे मुद्दों पर सवाल उठाने की पार्षदों की हिम्मत ही नहीं होती. धीरे-धीरे सारे विकास कार्य कार्पोरेट के हाथ में दिए जा रहे हैं. अनूप का सुझाव था कि नागरिक समाज अपने हाथ में पहल लें इसकी ज़रूरत है. RTI दाखिल करने, अभियान चलाकर नगर में हो रहे सभी कार्यों पर नागरिक दखल को बढाने के रास्तों पर सोचना चाहिए.

मनीष शर्मा ने कहा कि स्थानीय निकायों के पास कोई अधिकार नहीं दिए गए है और न संसाधन ही उपलब्ध हैं. ये निकाय सदैव लखनऊ या दिल्ली की सत्ता के दबाव में ही रहते हैं. ऐसी स्थिति में स्थानीय निकायों को दिल्ली और लखनऊ की सत्ता के विपक्ष का मंच बनाने के बारे में सोचना चाहिए. यानि नगर निगम/नगर पालिकाएं और पार्षद /सभासद मिलकर जनता के हित में जनता का मंच कैसे बनें इस बारे में सोचना चाहिए. पार्षद के लिए खड़े हो रहे उम्मीदवारों से संवाद किया जाना चाहिए.

मनीष ने इस दिशा में बढ़ने के लिए समाज को मज़बूत करने पर जोर दिया और इसके लिए रचनात्मक कार्यों को डिजाइन करने की आवश्यकता को रखा. स्वराज अथवा स्थानीय जनता की सत्ता को बल देने वाली व्यवस्था की ओर बढ़ने का यही मार्ग हो सकता है. इतिहास से सन्दर्भ लें तो समाजों के बीच भाईचारा बनाये रखने में समाजों की पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं. आपसी मतभेद और विवादों को समाज के अन्दर ही हल करने के तरीके रहे हैं. बुनकरों के बीच कार्य के दौरान मिले अपने अनुभवों से उन्होंने यह जोड़ा कि एक कारीगर समाज के आन्दोलन अथवा संघर्ष के दौरान अन्य विधा के कारीगर बहुधा उदासीन रहते हैं और एक ही विधा के कारीगरों के बीच भी दूरियां बनी हुई हैं, ऐसे में समाजों के बीच एकता के सूत्र गढ़ना कठिन है. लेकिन अगर इस समझ के साथ कार्य हो कि समाज की दुर्दशा के कारण समाज के अन्दर नहीं बल्कि बाहर हैं, तो शायद एक रास्ता बनता देखा जा सकता है.

इस संवाद में सभी ने हिस्सा लिया. यह महसूस किया गया कि नगर निगम और इसके सहायक विभागों की नगर निवासियों के साथ कोई संवाद न होना एक बड़ी समस्या है. सामाजिक कार्यकर्त्ता जागृति ने कहा कि नगर निगम के पास अधिकार और संसाधन नहीं होना भी बड़ी समस्या है. फ़ज़लुर्रहमान ने वार्ड पंचायत की आवश्यकता को दोहराया और कहा कि इसके कुछ प्रयोगों की शुरुआत होनी चाहिए.